



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 12 सितम्बर, 1994/21 भाद्रपद, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान मन्त्री मन्त्रालय

प्रधिमूचना

शिमला-4, 12 सितम्बर, 1994

संख्या 1-20/94-वि० ग०.—हिमाचल प्रदेश विधान मन्त्री मन्त्रालय एवं राज्य न्यायालय निदेशिका, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत 'हिमाचल प्रदेश उद्घाटन पाने वाले मह. विद्यालय (कर्मचारियों की

सेवा सुरक्षा विधेयक, 1994 (1994 का विधेयक संख्या: 12)" जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1994 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पारित संस्थापित हो गया है, गंगाधरण का मूलमार्थ राजपूत में प्रति करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-

(लक्ष्मण सिंह),

सचिव ।

1994 का विधेयक संख्या 12

## हिमाचल प्रदेश सहायता पाने वाले महाविद्यालय (कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा) विधेयक, 1994

(विधान सभा में पेशा पुरस्कृत रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सहायता पाने वाले महाविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का उपबन्ध पाने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंतालसौवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहायता पाने वाले महाविद्यालय (कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1994 है।

संक्षिप्त नाम  
और  
विस्तार।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

2. इस अधिनियम में, अथवा इस अधिनियम में अन्यथा अपेक्षित न हो, — परिभाषाएँ।

(क) "सहायता पाने वाले महाविद्यालय" या "महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय से सहबद्ध है और जिसे उसके विशेषाधिकार दिए गए हैं तथा जो राज्य सरकार में वृत्ति अनुसंधान अनुदान या सहायता प्राप्त कर रहा है ;

(ख) "निदेश" से शिक्षा निदेश, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन निदेश की शक्तियों का प्रयोग करने और इन्हों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ग) "जिला न्यायाधीश" से उस जिले का जिला न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसमें सहायता पाने वाला महाविद्यालय स्थित है ;

(घ) "कर्मचारी" से इस महाविद्यालय में नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत निर्धारित कर्मचारी (वर्कचार्ज) नहीं है ;

(ङ) "प्रबन्ध समिति" से महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी महाविद्यालय के प्राध्यापकों के प्रबन्ध के तत्कालीन व्यवस्था कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समित्व भी है ;

(च) "विविध" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्राचार्य" से महाविद्यालय का प्रमुख अभिप्रेत है ;

(ज) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

- (अ) "विश्वविद्यालय" से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 17) की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;
- (आ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 3) की धारा-4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ।

अर्हताएं ।

3. किसी महाविद्यालय के कर्मचारियों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं ऐसी होंगी, जैसी समय-समय पर, विश्वविद्यालय द्वारा अधिस्थित की जाएं :

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापकों के लिए अर्हताएं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अभिव्यक्त की जाएंगी :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान किसी नियमित कर्मचारी की अर्हताओं में उसके अहित में फेरफार नहीं किया जाएगा ।

भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तें ।

4. किसी महाविद्यालय के कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान कर्मचारी की सेवा शर्तों में उसके अहित में फेरफार नहीं किया जाएगा ।

आचरण संहिता ।

5. महाविद्यालय के कर्मचारी ऐसी आचरण संहिता द्वारा शासित होंगे जैसी विहित की जाएं :

परन्तु अध्यापकों की दशा में इस धारा के अधीन आचरण संहिता निम्न प्रकार से विहित की जाएगी :—

- (i) जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए गए हैं, वहां ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ; और
- (ii) जहां एवं कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं, वहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से ।

वेतन ।

6. महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य भत्ते और विशेषाधिकार ऐसे होंगे, जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

जांच के पश्चात् के सिवाय, पद-अपुति, हटाने या पक्ति-अपुति करने के आदेश का न किया जाना ।

7. महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को पदच्युत, हटाया या पक्तिच्युत नहीं किया जाएगा, सिवाए ऐसी जांच के पश्चात् के, जिसमें उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के बारे में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया हो ।

8. (1) किसी भी कर्मचारी पर, पदच्युति, हटाने या पंक्तिच्युत करने की शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक निर्देशन द्वारा उक्त अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है।

पदच्युति, हटाने या पंक्तिच्युत करने से पूर्व पालन की जाने वाली प्रक्रिया।

(2) जहाँ धारा 7 में निर्दिष्ट जांच के पश्चात् किसी कर्मचारी पर पदच्युति, सेवा से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव दिया जाए, वहाँ सुसंगत अभिलेख सहित प्रस्ताव, निर्देशन की निर्दिष्ट रीति में जाया और मात्र-मात्र सम्बन्धित कर्मचारी को भी सूचित किया जाएगा।

(3) कर्मचारी उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति में तीन दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध निर्देशन को, अभ्यावेदन कर सकता, जो, अभिलेख की परीक्षा करने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा प्रस्तावित शास्ति को अनुमोदित कर सकेगा या इसे कम कर सकता, अथवा इसे अनुमोदित करने में इस्तेमाल कर सकेगा यदि प्रस्ताव को असम्भाव्यपूर्ण या तंग करने के रूप में पाया जाता है अथवा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक नहीं है।

9. धारा 7 और 8 के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :-

कुछ मामलों में धारा 7 और धारा 8 का लागू न होना।

- (i) ऐसे कर्मचारी को सेवा सम्पत्ति को, जिस केवल अभ्यार्या अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है ;
- (ii) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मचारी, परिवीक्षा अवधि के दौरान या अन्त में, उसके कार्य या आचरण के अस्वीकार्य होने के आधार पर, सेवा सम्पत्ति को ; और
- (iii) ऐसे कर्मचारी, जिस ऐसे आचरण के आधार पर, पदच्युत या हटाया अथवा पंक्तिच्युत किया जाता है जिस पर उक्त नैतिक अधमता में अन्तर्भावित होने के अपराधिक आरोप का निन्दित उद्घाटन किया गया है।

10. एक वर्ष में अधिन के लिए सम्बन्ध विद्यमान रहने वाली रिक्ति पर नियुक्त कर्मचारी, एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगा जो समय-समय पर बढ़ाई जा सकती :

परिवीक्षा की अवधि।

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी है, दो वर्ष से अधिक नहीं होगा।

11. (1) किसी भी कर्मचारी को निर्वासित नहीं किया जाएगा, जब तक :-

कर्मचारियों का निवर्तन।

- (क) उसके विरुद्ध अनुशासित कार्यवाही अनुष्ठानत न हो या सम्पन्न न हो ; या
- (ख) किसी आपराधिक अपराध के बारे में उसके विरुद्ध मासिक अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन न हो।

(2) यदि महाविचारण की प्रवृत्ति किसी कर्मचारी को छः मास से परे की लाजाबन्ध के लिए निर्दिष्ट रखता सम्पत्तिन मंगलती है, तो यह

छ: मास की अवधि के अवसान के बाद से इस एक मास पूर्व, कार्यो को विनिश्चित करने हुए जितने संकेतों की निम्नलिखित अवधि को छ: मास से परे बढ़ाया जाता आवश्यक है, निर्देशक को व्यक्तिगत रिपोर्ट भेजेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, निर्देशक ऐसा आदेश पारित करेगा कि क्या बढ़ोतरी दी जाए या नहीं। उस द्वारा बढ़ोतरी देने में इनार की दशा में प्रबन्ध समिति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन के भीतर कर्मचारी को बहाल करेगी। ऐसा न करने पर सम्बन्धित कर्मचारी को, उपरोक्त अवधि के अवसान पर बहाल किया गया समझा जाएगा।

छटनी।

12. (1) महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी की कार्यभार में कमी के कारण, निर्देशक को पूर्व अनुमोदन के बिना छटनी नहीं दी जाएगी, जो अनुमोदन देने में पूर्व प्रत्येक मामले का, विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम कार्यभार मान के अनुसार, परीक्षण करेगा।

(2) छटनी के परिणामस्वरूप महाविद्यालय के कार्यभार से मुक्त किए गए कर्मचारी को उस महाविद्यालय में जहाँ वह छटनी से ठीक पूर्व सेवा कर रहा था या उसी प्रबन्ध समिति के अधीन किसी दूसरे महाविद्यालय में, भारों नियुक्ति के लिए अधिमान प्राप्त होगा।

वेतन के  
संदाय के  
लिए  
प्रक्रिया।

13. (1) महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति, अपने कर्मचारियों को वेतन संवितरित करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूचि में या नकारी बैंक में या सरकारी खजाने या उप-खजाने में एक अथवा "वेतन संदाय लेखा" खोलने जो संयुक्त रूप से प्राचार्य और निर्देशक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे निर्देशक द्वारा उप निमित्त प्राधिकृत किया जाए, संचालित किया जाएगा।

परन्तु "वेतन संदाय लेखा" खोलने के पश्चात् निर्देशक, यदि, धारा 22 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, उसका समन्धान हो जाता है कि लोक-हित से ऐसा किया जाना समीचीन है, तो वह बैंक या खजाने को अनुदेश दे सकेगा कि "वेतन संदाय लेखा" का संचालन केवल प्राचार्य द्वारा ही किया जाएगा और वह ऐसे किसी भी अनुदेश का किसी भी समय प्रतिसंहारण कर सकेगा।

परन्तु यह और कि उप-धारा (3) में निर्दिष्ट मामलों में या किसी अन्य मामले में जहाँ प्रबन्ध समिति को कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् निर्देशक को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह बैंक या खजाने को अनुदेश दे सकेगा कि "वेतन संदाय लेखा" का संचालन केवल स्वयं उस द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो, उस द्वारा उप निमित्त प्राधिकृत किया जाए, और ऐसे अनुदेश का किसी भी समय प्रतिसंहारण कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, समय-समय पर, माधारण या विशेष आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि प्रबन्ध समिति विद्यार्थियों से फोंस के रूप में प्राप्त रकम का एक भाग और महाविद्यालय को या महाविद्यालय के फायदे के लिए पूर्णतः या अंशतः वित्तियता की गई किसी सम्पत्ति, जंगम या स्थावर के प्राप्त भाग का भी, यदि कोई हो, तथा नग्न और ऐसी तारीख तक, जैसी उप आदेश में विनिर्दिष्ट

की जाए, "वेतन सदाय लेखा" में वेतन बढ़ाया जाए तदुपरि प्रबन्ध समिति ऐसे निदेश का पालन करने की अध्यक्ष होगी।

(3) जहाँ निदेशक की यह राय हो कि प्रबन्ध समिति उप-धारा (2) के उपबन्धों या तदधीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार फॉल जमा कराने में अग्रसर रही है, वहाँ निदेशक, आदेश द्वारा प्रबन्ध समिति को विद्यार्थियों से कोई फॉल वसूल करने से प्रतिषेध कर सकेगा और तदुपरि निदेशक विद्यार्थियों से सीधे तौर पर महाविद्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से या ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे फॉल वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गई फॉल को "वेतन सदाय लेखा" में जमा करेगा।

(4) राज्य सरकार भी उप-धारा (2) और (3) के अधीन जमा करवाई गई रकम को ध्यान में रखने के पश्चात् ऐसी रकम अनुसंधान अनुदान के रूप में "वेतन सदाय लेखा" में संदत्त करेगी, जो उप-धारा (5) के अनुसार संदाय करने के लिए आवश्यक है।

(5) किसी कर्मचारी का वेतन "वेतन सदाय लेखा" में, बैंक में उसके लेखा को, यदि कोई हो, रकम के अन्तर्ण द्वारा या यदि उस बैंक में उसका लेखा नहीं है तो बैंक द्वारा संदत्त किया जाएगा।

14. धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन निदेशक के आदेश से व्यक्ति कोई पक्षकार, तीस दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील फाइल कर सकेगा, जो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

अपील।

परन्तु जिला न्यायाधीश, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से समय पर अपील फाइल करने से निर्धारित रहा था, उक्त तीस दिन की अवधि के अद्वितीय के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

15. राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त प्राप्त आवेदन पर, निदेशक के समक्ष या तो लिखित या जिसमें निदेशक ने कोई आदेश पारित कर दिया है, किन्हीं कार्यवाहियों के आभिलष ऐस आदेश की वैधता या अतिरिक्त के बारे में अपने समाधान के प्रयोजन के लिए जांचा सकेगी और उसके सम्बन्ध में ऐस आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे :

पुनरीक्षण के अतिरिक्त।

परन्तु राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश, ऐसे पक्षकार को सुनवाई का मुक्तिपुक्त अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं करेगी।

16. राज्य सरकार, महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को ऐसे निदेश जारी करने के लिए सक्षम होगी जैसा इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अतिरिक्त अन्तर्गत के लिए आवश्यक हों।

निदेश जारी करने की शक्ति।

17. (1) इसके प्रसारण से प्रभावित प्रबन्ध समिति, प्राचार्य या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों या धारा 16 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अतिक्रमण के लिए,

कुछ मामलों में सहायता अनुदान





## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में राज्य कोष में सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे बहुत से प्राइवेट महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं। उनकी वेतन नामावली में बहुत से कर्मचारी हैं। इन संस्थानों को कर्मचारियों, अनन्य रूप में उनका वेतन संवितरित करने के लिए, दो गई सरकारी निधि के उपयोग और प्रबन्ध मण्डल की अन्य कार्यवाहियों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं। इसलिए उनके वेतन के संदाय और सेवा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है, ताकि उनकी प्रबन्ध समितियों द्वारा मनमाने रूप में उन्हें निवृत्त, पदच्युत या सेवा में हटाना या पेंसिच्युत न किया जा सके। यह उपबन्ध करना भी आवश्यक हो गया है कि इस निमित्त विहित उपबन्धों के अनुक्रमण में कर्मचारियों पर शास्त्रियों अधिरोपित करने या कर्मचारियों को वेतन संवितरित करने की दृष्टि में सरकार, इन महाविद्यालयों के राज्य निधि में से सहायता अनुदान को कम करने, रोकने या निर्दिष्ट करने का आदेश देने के लिए सक्षम होगी।

यह विशेष उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और उपर्युक्त प्राप्ति के अनुबन्ध विधियों या उपबन्ध करने के लिए है।

शिमला :

..... 1994.

साराजण चन्द पराशर,

मिजा मन्त्री।

## वित्तीय ज्ञापन

इस विधेय में प्रस्तुतित उपबन्ध, अधिविधित किए जाने पर, विधान सभा द्वारा कार्यन्वित किए जाएंगे और इस प्रकार विधेय के उपबन्धों के कार्यन्वयन के लिए, राज्य कोष से कोई अतिरिक्त व्यय उभर नहीं किया जाएगा।

## प्रत्ययोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 उनमें परिणित विधियों के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को नग्न करता है। यह प्रत्ययोजन विधेय के उपबन्धों के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए आवश्यक है और सामान्य स्वरूप का है।

# THE HIMACHAL PRADESH AIDED COLLEGES (SECURITY OF SERVICES OF EMPLOYEES) BILL, 1994

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

## A BILL

*to provide for the security of services to the employees of the aided Colleges in the State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Aided Colleges (Security of Services of Employees) Act, 1994.

Short title  
and extent.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Defini-  
tions.

- (a) "aided College" or "College" means a College affiliated to and admitted to the privileges of a University and receiving annual maintenance grant or aid from the State Government;
- (b) "Director" means the Director of Education, Himachal Pradesh, and includes any other officer authorised by the State Government to exercise the powers and perform the functions of the Director under this Act;
- (c) "District Judge" means the District Judge of the District in which the aided College is situated;
- (d) "employee" means a person in the employment of a College, but does not include a work-charged employee;
- (e) "Managing Committee" means the Managing Committee of a College and includes a person or body of persons for the time being entrusted with the management of the affairs of the College;
- (f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (g) "Principal" in relation to a College means the head of the College;
- (h) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
- (i) "University" means the Himachal Pradesh University constituted under section 3 of the Himachal Pradesh University Act, 1970; and
- (j) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956.

17 of 1970

3 of 1956

3. The minimum qualifications for recruitment of various classes of the employees of a College shall be such as may, from time to time, be laid down by the University;

Qualifica-  
tions.

Provided that the qualifications for the teachers shall be laid down by the University in accordance with the guidelines issued from time to time by the University Grants Commission:

Provided further that the qualifications of an existing regular employee at the commencement of this Act shall not be varied to his disadvantage.

Method of recruitment and conditions of service.

4. The method of recruitment, and the conditions of service of the employees of a College shall be such as may be prescribed:

Provided that the conditions of service of an existing employee at the commencement of this Act shall not be varied to his disadvantage.

Code of conduct.

5. The employees of College shall be governed by such Code of Conduct as may be prescribed:

Provided that in the case of teachers the Code of Conduct under this section shall be prescribed—

(i) where any guidelines have to be issued by the University Grants Commission in conformity with such guidelines; and

(ii) where no such guidelines have been issued, in consultation with the University Grants Commission.

Salary.

6. The scales of pay and other allowances and privileges of the employees of a College shall be such as may, from time to time, be specified by the State Government.

Dismissal, removal or reduction in rank not to be ordered except after inquiry.

7. No employee of a College shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

Procedure to be observed before dismissal, removal or reduction in rank.

8. (1) The penalty of dismissal or removal from service or reduction in rank shall not be imposed on an employee unless the same is approved by the Director.

(2) Where after the inquiry referred to in section 7, it is proposed to impose on an employee the penalty of dismissal, removal from service or reduction in rank, the proposal along with the relevant record shall be referred to the Director and the employee concerned shall be informed simultaneously.

(3) The employee may, within a period of thirty days of the receipt of the intimation referred to in sub-section (2) make a representation against the proposed penalty to the Director who may, after examining the record and giving the parties an opportunity of being heard, by an order in writing, approve the proposed penalty or reduce it or, refuse to approve it, if the proposal is found to be malafide or by way of victimisation or not warranted by the facts and circumstances of the case.

Provided that after the "Salary Payment Account" is opened, the Director may, if he is subject to any rules made under section 22, satisfied that it is expedient in the public interest so to do, instruct the bank or treasury that the account shall be operated by the Principal alone and may at any time revoke such instruction:

Provided further that in the case referred to in sub-section (3) or where in any other case after giving to the Managing Committee an opportunity of showing cause, the Director is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may instruct the bank or treasury that the "Salary Payment Account" shall be operated only by himself or by such other officer as may be authorised by him in that behalf, and may at any time revoke such instruction.

(2) The State Government may, from time to time, require by general or special order that the Managing Committee shall deposit in the "Salary Payment Account" such portion of the amount received from students as fees and also such portion, if any, of the income received from any property, movable or immovable, belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the College, and by such date as may be specified in that order, and thereupon the Managing Committee shall be bound to comply with such direction.

(3) Where the Director is of opinion that the Managing Committee has failed to deposit the fees in accordance with the provisions of sub-section (2) or the orders issued thereunder, the Director may, by order prohibit the Managing Committee from realising any fee from the students and thereupon, the Director may realise the fees either through the employees of the College or in such other manner as he thinks fit, directly from the students and shall deposit the fees so recovered in the "Salary Payment Account".

(4) The State Government shall also pay into the "Salary Payment Account" such amount as maintenance grant which, after taking into consideration the amount deposited under sub-sections (2) and (3), is necessary for making payment in accordance with sub-section (5).

(5) The salary of an employee shall be paid by transfer of the amount from the "Salary Payment Account" to his account, if any, in the bank, or if he has no account in that bank, then by cheque.

Appeal.

14. Any party aggrieved by an order of the Director under sub-section (3) of section 8 may file an appeal, within thirty days, to the District Judge who may, after giving to the parties an opportunity of being heard pass such order as he may deem fit:

Provided that the District Judge may entertain the appeal after expiry of the said period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

Power revision.

15. The State Government may, either of its own motion or on an application received in this behalf, at any time call for the record of any proceedings which is either pending before the Director or in which the Director has passed any order for the purpose of satisfying itself as to



9. The provisions of sections 7 and 8 shall not apply—

- (i) to the termination of service of an employee who is appointed for a temporary period only;
- (ii) to the termination of service of an employee appointed on probation, during or at the end of the period of probation, or on account of his work or conduct being unsatisfactory; and
- (iii) to an employee who is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct, which has led to his conviction on a criminal charge involving moral turpitude.

Sections 7 and 8 not to apply in certain cases.

10. An employee appointed against a vacancy likely to exist for more than one year shall remain on probation for a period of one year which may be extended from time to time :

Period of probation

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed two years.

11. (1) No employee shall be placed under suspension, unless,—

Suspension of employees

- (a) disciplinary proceedings against him are contemplated or are pending; or
- (b) a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

(2) In case the Managing Committee of a College considers it expedient to keep an employee under suspension beyond a period of six months, it shall submit a detailed report to the Director at least one month before the expiry of the period of six months specifying the reasons warranting the extension of the suspension period of the employee beyond six months.

(3) After considering the report under sub-section (2), the Director shall pass an order whether the extension be granted or not. In the event of his refusal to grant the extension, the Managing Committee shall reinstate the employee within a fortnight from the date of receipt of the order, failing which the employee concerned shall be deemed to have been reinstated on the expiry of the aforesaid period.

12. (1) No employee of a College shall be retrenched on account of reduction in work-load without the prior approval of the Director who shall before according approval examine each case in accordance with the norms of work-load laid down by the University.

Retrenchment.

(2) An employee who is relieved from a College as a result of retrenchment shall have preference for appointment to future vacancies in the College in which he was serving immediately before retrenchment or in another College under the same Managing Committee.

13. (1) The Managing Committee of a College shall, for the purpose of disbursement of salaries to its employees, open in a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 or a co-operative bank or a Government treasury or sub-treasury a separate "Salary Payment Account" to be operated jointly by the Principal and the Director or such other officer as may be authorised by the Director in that behalf:

Procedure for payment of salary.



- (iii) the procedure to be observed for an inquiry under section 7;
- (iv) the manner in which "Salary Payment Account" shall be opened and maintained under section 13;
- (v) the manner of filing an appeal to the District Judge under section 14 ; and
- (vi) any other matter which has to be or may be prescribed under the Act.

(3) The power to make rules conferred by this section shall be subject to the condition of the rules being made after previous publication.

the legality or propriety of such order or may pass such order in relation thereto as it thinks fit:

Provided that the State Government shall not pass an order under this section prejudicial to any party without giving such party a reasonable opportunity of being heard.

16. The State Government shall be competent to issue such directives to the Managing Committee of a College as may be necessary for the proper enforcement of the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Power to issue directives.

17. (1) It shall be lawful for the Government to stop, reduce or suspend the grant-in-aid to a College for the violation of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder or of any directive issued under section 16, by the Managing Committee, Principal or any other authority charged with the administration thereof.

Power to stop, reduce or suspend grant-in-aid or to make payment therefrom to employees in certain cases.

(2) In the case of non-compliance of an order of a competent authority, or of any directive issued under this Act, it shall be lawful for the Government to pay, out of the grant-in-aid payable to a College, such sum of money as is found to be due to any employee from such a college or the Managing Committee.

(3) Before taking any action under this section, the Government shall give a reasonable opportunity to such Managing Committee, Principal or authority concerned to show cause against the action proposed to be taken.

18. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force including any regulation or statute of any University.

Over-riding effect of this Act.

19. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any proceedings taken under the provisions of this Act.

Bar of jurisdiction of civil courts.

20. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any authority or any officer appointed under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

21. (1) The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(i) the method of recruitment and conditions of services of employees under section 4;

(ii) the Code of Conduct for the employees of a College under section 5;

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A number of private colleges receiving grants-in-aid from the State exchequer are functioning in the State of Himachal Pradesh. They have a number of employees on their pay-rolls. The employees of these institutions deserve protection against diversion of Government funds given exclusively for disbursement of salary of employees and against other actions of the management. It has become necessary to ensure payment of their salaries and security of their services so that they may not be suspended, dismissed or removed from services or reduced in rank by their Managing Committees arbitrarily. It has also become necessary to provide that in the event of imposition of penalties on the employees or disbursement of the salaries to the employees in contravention of the provisions prescribed in this behalf, the State shall be competent to order reduction, stoppage of suspension of grants-in-aid to these Colleges out of State funds.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objects and provide for matters ancillary or incidental thereto.

NARAIN CHAND PRASHER,  
Minister-in-charge.

SHIMLA:  
The.....1994.

## FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions contained in the Bill, when enacted, will be implemented through the existing Government machinery and thus for the implementation of the provisions of the Bill, no additional expenditure shall be incurred out of the State exchequer.

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 21 of the Bill empowers the State Government to make rules relating to the matter enumerated therein. This delegation is necessary for the effective implementation of the provisions of the Bill and is normal in character.